भोपाल | शनिवार | 8 अगस्त 2026 | वर्ष 70 | अंक 196 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 कई देश विदेशी फंड नियंत्रित करते हैं

4 युवाओं को राहत लेकिन मुद्दे भी हल करें

9 यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा ग्राहकों से शुल्क

11 भारत-श्रीलंका टेस्ट में 5 गेंदबाजों का रहा दबदबा

जनता के दरवाजे पर मोहन सरकार

1 जन विश्वास अभियान में सीएम की सख्ती
2 मैदानी अमले को सीएम की चेतावनी
3 लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं : सीएम

छिंदवाड़ा के सीएमएचओ, तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल/छिंदवाड़ा. 7 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में शुरू हुए सीएम जन विश्वास अभियान के पहले दिन ही कड़े तेवर दिखाए हैं. सीएम अभियान के तहत शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचें, जहां वे आम लोगों से रूबरू हुए. इस दौरान अलग- अलग शिकायतों को लेकर छिंदवाड़ा के सीएमएचओ, तहसीलदार और एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया, वहीं लापरवाही अधिकारियों- कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए.

अभियान के तहत सीएम छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचें, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याओं के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों की आवेदकों की मौजूदगी में एक-एक कर मामलों की पड़ताल की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मैदानी अमले को साफ संदेश दिया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई, उन पर उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. अभियान के तहत पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी सरकार ही मंत्रालय वल्लभभवन से बाहर निकलकर जनका के दरवाजे पर यानी मैदान में जुटे रहे, इस दौरान मंत्री से लेकर अफसर तक लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने और संवाद करने में लगे रहे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को श्रीमती सीमा तुमराम ने बताया कि उन्होंने प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की थीं. जांच में सामने आया कि पोर्टल पर दर्ज त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका. मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने इसे विभागीय लापरवाही मानते हुए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा डॉ. नरेश गुन्नाड़े को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव को गोविंद नायक ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भू-अभिलेख दुरुस्तीकरण से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की. समीक्षा में पाया गया कि एसडीएम द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद अभिलेखों में सुधार नहीं किया गया.

(शेष पेज 12 पर)

सम्मान निधि का लाभ नहीं देना तहसीलदार और पटवारी को पड़ा भारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में मीना बंजारा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई. समीक्षा में पाया गया कि परासिया तहसील के संबंधित पटवारी द्वारा गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण आवेदिका योजना के लाभ से वंचित रही. मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मामले को गंभीर मानते हुए परासिया तहसील के संबंधित पटवारी सिद्धांत साहूएवं तहसीलदार सुनैना ब्रहमे को निलंबित करने के निर्देश दिए. साथ ही मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के माध्यम से आवेदिका को एक वर्ष की सहायता राशि प्रदान करने के भी निर्देश दिए.

एक-एक वेतनवृद्धि रोकी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को श्रीमती मानवती वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में पति संतोष वर्मा की मृत्यु के बाद उन्हें पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिली, जिसकी उन्होंने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज कराई थीं. मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चौरई तथा श्रम अधिकारी की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए.

सीबीआई चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा

नीट -यूजी पेपर प्रिंटिंग प्रेस से नहीं एनटीए के एक्सपर्ट से हुआ था लीक

- सीबीआई चार्जशीट में महीनों पुरानी साजिश का दावा
- कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई

नई दिल्ली,07 अगस्त. नीट-यूजी 2026 के कथित पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पन्नों की चार्जशीट में दावा किया है कि परीक्षा से कई महीने पहले ही पेपर लीक की कथित साजिश रच ली गई थी.

चार्जशीट के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तीन विशेषज्ञों ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन के दौरान प्रश्नों को याद किया. बाद में होटल लौटकर उन्हें कागज पर लिखते थे और कथित तौर पर बिचौलियों तथा कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था.

सीबीआई के अनुसार, मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इनमें एनटीए के तीन विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिन पर अपने पद का दुरुपयोग कर प्रश्नपत्र लीक करने का आरोप लगाया गया है.

एजेंसी का कहना है कि लीक किए गए प्रश्न टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पीडीएफ, फोटो और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए साझा किए गए. कुछ मामलों में छात्रों से हाथ से प्रश्न लिखवाकर तैयारी कराने का भी आरोप लगाया गया है.

पांच लाख का इनामी नक्सली ने किया सरेंडर

चाईबासा, 07 अगस्त। कोल्हान में माओवाद के खिलाफचल रहे अभियान के बीच प्रतिबंधित भाकपा संगठन को बड़ा झटका लगने की सूचना है। संगठन के इनामी जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर कायम ने दो महिला माओवादियों के साथ पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि, देर रात तक जिला पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी और न ही कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। तीनों ने सुरक्षा बलों के लगातार अभियान, जंगलों में बढ़ते दबाव और संगठन के कमजोर पड़ते नेटवर्क के बीच आत्मसमर्पण किया।

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित

नई दिल्ली, 07 अगस्त. लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने चढ़ावा चोरी तथा छात्रों पर पुलिस कार्रवाई मामले में गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग करते हुए हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विधेयक 2026 सदन में पेश किया, जिसे सदन में हंगामे की बीच ही बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया.

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष गृहमंत्री को सदन में आने की बात कर रहा है लेकिन यह सिर्फ सदन को बाधित करने का प्रयास है.

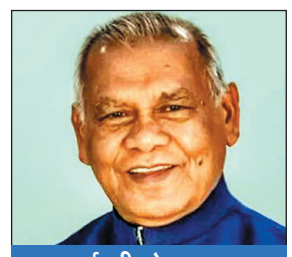

कार्यवाही सोमवार तक कर दी गई स्थगित

एक नजर में

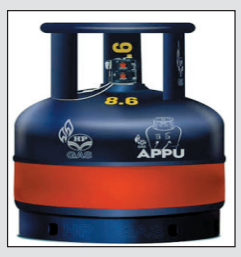

762 रुपए में मिल रहा 5 किलो का गैस सिलेंडर

नई दिल्ली. घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और 14.2 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 942 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध है. हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की है, जिससे यह सिलेंडर अब 762 रुपए में उपलब्ध है. पहले इसकी कीमत 808.50 रुपए थी. 1 अगस्त से लागू नई दरों के अनुसार 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 46.50 रुपए की कमी की गई है.

कांग्रेस ने सांसदों को जारी की व्हिप

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र इस बार लगातार सियासी घमासान की भेंट चढ़ता आ रहा है। दूसरा सच यह भी है कि अभी ये घमासान दूर-दूर तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यह गतिरोध और बढ़ने के पूरे आसार हैं। इसकी वजह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी आक्रामक रणनीति का संकेत देते हुए लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों के लिए एक कड़ा व्हिप जारी किया है।

गुस्ताखी माफ

114 राफेल की डील के लिए भेजा प्रपोजल

नई दिल्ली, 07 अगस्त। भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपनी स्क्वाड्रन ताकत को बढ़ाने की चुनौती का सामना कर रही है. इसी बीच फ्रांस की ओर से 114 राफेल मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद का प्रस्ताव भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फ्रांस ने इस प्रस्ताव के जरिए न केवल बड़ी संख्या में राफेल विमान उपलब्ध कराने की पेशकश की है, बल्कि भारत में इनके बड़े हिस्से के निमाज़्ण का रास्ता भी सुझाया है. प्रस्ताव के मुताबिक कुल 114 विमानों में से 94 राफेल भारत में ही बनाए जा सकते हैं.

भारत में ही बनेंगे 94 विमान

करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला यह प्रस्ताव फिलहाल रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना के स्तर पर विचाराधीन है. इस प्रस्ताव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपने लड़ाकू विमान बेड़े की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. मौजूदा समय में पुराने पड़ रहे कई लड़ाकू विमानों को धीरे-धीरे सेवा से बाहर करने की प्रक्रिया के बीच नए और आधुनिक विमानों की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है. राफेल को भारतीय वायुसेना पहले से संचालित कर रही है, ऐसे में नए विमानों को बेड़े में शामिल करने से प्रशिक्षण, रखरखाव और परिचालन स्तर पर भी कुछ फायदे मिल सकते हैं. फ्रांस के प्रस्ताव में भारत में उत्पादन का हिस्सा सबसे अहम पहलुओं में से एक है.

भारत ने अरुणाचल के 27 स्थान नक्शे में किए दर्ज

नई दिल्ली, 7 अगस्त. अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार किए जा रहे दावों के बीच भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और रणनीतिक कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक नक्शों में अरुणाचल प्रदेश के 27 प्रमुख स्थानों और भौगोलिक संरचनाओं को उनके मानक भारतीय नामों के साथ दर्ज कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन स्थानों की आधिकारिक पहचान भारतीय नक्शे में सुनिश्चित की गई है.

3,300 करोड़ के हिसाब में घोटाला नहीं

राम मंदिर दान विवाद : रिकॉर्ड के अनुसार पूरा लेखा-जोखा सही पाया गया

अयोध्या, 7 अगस्त. अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि को लेकर सामने आए विवाद के बीच सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि मंदिर ट्रस्ट के लगभग 3,300 करोड़ रुपए के दान में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या घोटाले की पुष्टि नहीं हुई है.

सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का स्वतंत्र बाहरी ऑडिट कराया गया है और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पूरा लेखा-जोखा सही पाया गया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि का ऑडिट एम/एस वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी द्वारा किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रस्ट ने अब तक लगभग 1,800 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पर और करीब 400 करोड़ रुपए भूमि खरीद पर खर्च किए हैं. इन सभी भुगतानों के लिए बैंकिंग माध्यम का उपयोग किया गया और किसी भी प्रकार का नकद भुगतान नहीं किया गया.

सूत्रों के अनुसार, हुंडी से निकाली गई नकदी को मशीन से गिनने से पहले हाथों से अलग-अलग किया जा रहा था. इसी प्रक्रिया के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की ओर से नियुक्त एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के छह बाहरी कर्मचारियों पर नकदी चोरी करने का आरोप लगा. अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया. सरकार का कहना है कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति बाहरी एजेंसी के कर्मचारी थे और उनका राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर प्रशासन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था.

मेटा पर 5,404 करोड़ रुपए का जुर्माना

फेसबुक-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा को कोर्ट से झटका

सांता फे (न्यू मैक्सिको) 7 अगस्त. सोशल मीडिया कंपनी मेटा को अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में एक अदालत से बड़ा झटका लगा है. न्यू मैक्सिको की फर्स्ट ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कंपनी को 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 5,404 करोड़ रुपए) राज्य के एक विशेष फंड में जमा करने का आदेश दिया है.

यह राशि उन कार्यक्रमों के लिए उपयोग की जाएगी, जिनका उद्देश्य किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटना है. अदालत का यह आदेश एक ट्रायल के बाद आया है, जिसमें राज्य की जूरी ने मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और यौन शोषण से संबंधित आरोपों पर विचार किया. मामले में पहले जूरी ने कंपनी पर 375 मिलियन डॉलर का दंड निर्धारित किया था.

दवा उद्योग को 6,659 करोड़ का प्रोत्साहन

2022-23 में पीएलआई योजना की थी शुरू

2026 तक 87.70 करोड़ की राशि की वितरित

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आईं कई बाधाएं

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कई बाधाएं-थोक दवाओं से संबंधित पीएलआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण में लगने वाला समय, पर्यावरण मंजूरी और उच्च उपयोगिता लागत जैसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा, फर्मेंटेशन यानी किण्वन आधारित थोक औषधियों के निर्माण में भी लंबा समय लगता है. किण्वन प्रक्रिया के कारण भी देरी-रासायनिक संश्लेषण के विपरीत किण्वन प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं की जैविक गतिविधि पर निर्भर करती है. इन कोशिकाओं की वृद्धि की गति प्राकृतिक रूप से धीमी होती है. इन कारणों से परियोजनाओं के शुरू होने में देरी हुई और इसका असर प्रोत्साहन राशि के वितरण पर भी पड़ा.

नई दिल्ली, 07 अगस्त. रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि दवा क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू की गई थी.

योजना के तहत कुल 15,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय में से मार्च 2026 तक 6,659 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है. थोक दवाओं के लिए 87.70 करोड़ रुपए जारी- थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 6,940 करोड़ रुपए के परिव्यय में से मार्च 2026 तक 87.70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है.

सऊदी-पाक-तुर्किये का नया रक्षा समझौता

नई दिल्ली, 7 अगस्त. पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते को 'मक्का पैक्ट' के नाम से जाना जा रहा है. समझौते के तहत तीनों देशों ने कहा है कि किसी एक देश पर होने वाले सशस्त्र हमले को साझा सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाएगा.

यह समझौता मक्का में आयोजित एक संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ. बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए. तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यह समझौता उनके ऐतिहासिक, धार्मिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है. समझौते का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना और संभावित बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना बताया गया है. इसके तहत सैन्य सहयोग, रक्षा तकनीक और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने की बात कही गई है.

किसी भी एक देश पर हमले को तीनों देश पर हमला माना जाएगा

भारत की नजर पूरे घटनाक्रम पर

बताया गया है कि पाकिस्तान और तुर्किये रक्षा तकनीक, हथियार और ड्रोन निर्माण में सहयोग बढ़ा सकते हैं, जबकि सऊदी अरब इसमें निवेश की भूमिका निभा सकता है. हालांकि तुर्किये के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता रक्षात्मक प्रकृति का है और किसी विशेष देश को निशाना बनाकर नहीं किया गया है. भारत ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे एक नया घटनाक्रम बताते हुए कहा कि भारत स्थिति की निगरानी कर रहा है और जरूरत के अनुसार आगे कदम उठाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में भारत एक प्रमुख सुरक्षा संदर्भ रहा है.

बैठक | बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-चिंता करने की जरूरत नहीं

एनडीए के 45 नए सांसदों से मिले पीएम मोदी

नई दिल्ली, 7 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 45 नए लोकसभा सांसदों के साथ नाश्ता बैठक की. बैठक में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) से अलग होकर एनडीए का समर्थन करने वाले सांसद भी शामिल थे.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि एनडीए एक परिवार है और गठबंधन के प्रत्येक सांसद का सम्मान किया जाएगा.

(शेष पेज 12 पर)

पंजाब में बीजेपी और अकाली दल साथ-साथ

चंडीगढ़, 7 अगस्त. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सुखबीर बादल शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे और संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. बैठक के बाद उन्होंने बताया कि पंजाब की कानून व्यवस्था और राज्य सरकार की योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई. हालांकि, मुलाकात का विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है. राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण मान रहे हैं.